



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 चैत्र 1946 (श०)  
(सं० पटना 386) पटना, सोमवार, 15 अप्रैल 2024

सं० 08/आरोप-01-02/2020 सा0प्र0—4181  
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

11 मार्च 2024

श्री विनोद कुमार ठाकुर, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-567/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पटना (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरुद्ध कार्य में रूचि नहीं लेने, अनुशासनहीनता बरतने, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने से संबंधित आरोपों के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक-526 दिनांक 29.01.2020 द्वारा आरोप पत्र अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-2988 दिनांक 27.02.2020 द्वारा श्री ठाकुर से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री ठाकुर का स्पष्टीकरण (दिनांक 28.09.2020) प्राप्त हुआ। उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-1783 दिनांक 09.02.2021 द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक-2386 दिनांक 01.07.2021 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ, जिसमें श्री ठाकुर के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

2. श्री ठाकुर के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत मामले की गम्भीरता को देखते हुए विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित करते हुए आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-43 (बी०) के प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-8612 दिनांक 11.08.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-417 दिनांक 23.06.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। विभागीय जाँच आयुक्त द्वारा श्री ठाकुर के विरुद्ध प्रतिवेदित दोनों आरोपों को प्रमाणित पाया गया है। संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष निम्नवत है :-

- आरोपी पदाधिकारी का बचाव बयान, उपस्थापन पदाधिकारी का लिखित पक्ष एवं अन्य संलग्न कागजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि किसी भी जिले के जिला प्रबंधक का मुख्य कार्य किसी भी योजना के अन्तर्गत आवंटित माह का खाद्यान्न लाभुकों को आवंटन माह में उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यदि खाद्यान्न का प्रेषण कार्य तथा खाद्यान्न का उठाव योजनाबद्ध तरीके से कराया जाय तो खाद्यान्न के भंडारण हेतु समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।

- (ii) परिवहन अभिकर्ताओं के परिवहन एवं हथालन से संबंधित विपत्र का भुगतान विलम्ब से होने के संबंध में आरोपी पदाधिकारी द्वारा किसी भी विशिष्ट माह के विपत्र का भुगतान विलम्ब से किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही कोई साक्ष्य समर्पित किया गया है।
- (iii) जहाँ तक प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम, पटना द्वारा विभिन्न कार्यालय पत्रों के माध्यम से समय-समय पर आरोपी पदाधिकारी से खाद्यान्न के उठाव में बरती जा रही लापरवाही के लिए माँग किये गये स्पष्टीकरण का कोई जबाव नहीं देने का आरोप है इसके संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव बयान में कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई साक्ष्य समर्पित किया गया है।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-12985 दिनांक 10.07.2023 द्वारा श्री ठाकुर से लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री ठाकुर का लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनका कहना है कि जिला प्रबंधक के पद पर रहते हुए मेरे द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती गयी है। पटना में भारी वर्षा के कारण पटना शहरी क्षेत्र डूब गया था। इसके बावजूद मेरे द्वारा विभागीय कार्य को निष्ठापूर्वक सम्पन्न किया गया।

5. श्री ठाकुर के विरुद्ध गठित आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री ठाकुर द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षापरांत पाया गया कि जिला प्रबंधक के पद पर रहते हुए उनके द्वारा कार्य के प्रति लापरवाही बरती गयी है। संचालन पदाधिकारी ने भी अपने जाँच प्रतिवेदन में विस्तृत समीक्षा करते हुए आरोप को प्रमाणित पाया है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने लिखित अभिकथन में तो आरोपों से इन्कार किया गया है परन्तु समर्थन में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतएव संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-43 (बी०) के संगत प्रावधानों के तहत श्री विनोद कुमार ठाकुर के "पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की राशि कटौती 03 (तीन) वर्षों तक करने" का दंड विनिश्चित किया गया।

उक्त विनिश्चित दंड पर विभागीय पत्रांक-22368 दिनांक 08.12.2023 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श/मंतव्य की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 24.01.2024 को आहूत पूर्ण पीठ की बैठक में श्री ठाकुर के विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव (यथा पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की राशि कटौती 03 (तीन) वर्षों तक करने) पर सहमति व्यक्त किया गया। उक्त सहमति/मंतव्य बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-4665 दिनांक 19.02.2024 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया।

अतएव वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री विनोद कुमार ठाकुर, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-567/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पटना (सम्प्रति सेवानिवृत्त) को प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी०) के संगत प्रावधानों के तहत "पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की राशि कटौती 03 (तीन) वर्षों तक करने" का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अंजुला प्रसाद,  
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 386-571+10-डी०टी०पी०  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>